

विद्युत मंत्रालय
मांग संख्या 64
विद्युत मंत्रालय

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार है:

मुख्य शीर्ष	बजट 2000-2001			संशोधित 2000-2001			बजट 2001-2002			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
राजस्व	461.70	55.74	517.44	521.04	51.75	572.79	517.91	53.80	571.71	
पूंजी	2639.27	...	2639.27	2644.46	...	2644.46	2770.09	...	2770.09	
जोड़	3100.97	55.74	3156.71	3165.50	51.75	3217.25	3288.00	53.80	3341.80	
1. सचिवालय आर्थिक सेवाएं	3451	0.25	7.44	7.69	0.25	7.25	7.50	0.50	7.53	8.03
विद्युत सामान्य										
2. केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण	2801	9.25	36.45	45.70	6.78	33.36	40.14	13.04	34.92	47.96
	4801	5.81	...	5.81	3.17	...	3.17	7.41	...	7.41
जोड़		15.06	36.45	51.51	9.95	33.36	43.31	20.45	34.92	55.37
3. अनुसंधान और विकास										
3.01 केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान, संस्थान बंगलौर	2801	13.70	...	13.70	13.70	...	13.70	8.37	...	8.37
3.02 मूलभूत और बुनियादी अनुसंधान	2801
जोड़		13.70	...	13.70	13.70	...	13.70	8.37	...	8.37
4. प्रशिक्षण										
4.01 राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण अनुसंधान (एन पी टी आई)	2801	2.50	4.35	6.85	2.50	4.44	6.94	6.37	4.65	11.02
5. ऊर्जा संरक्षण/ई एम सी	2801	15.25	...	15.25	3.00	...	3.00	9.88	...	9.88
6. राज्य विद्युत विनियामक आयोग की स्थापना	2801	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50
7. विद्युत विकास निधि	2801	0.50	...	0.50
8. ताप विद्युत केन्द्रों को बेहतर निष्पादन के लिए प्रोत्साहन स्कीमें पारिषण और वितरण हानि में कमी	3601	4.75	...	4.75	4.75	...	4.75	9.25	...	9.25
9. केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग	2801	...	6.50	6.50	...	5.70	5.70	...	5.70	5.70
	4801
जोड़		...	6.50	6.50	...	5.70	5.70	...	5.70	5.70
10. विद्युत वित्त निगम के ब्याज संबंधी आर्थिक सहायता	2801	300.00	...	300.00	299.06	...	299.06	350.00	...	350.00
11. ग्रा. वि. नि. को ब्याज संबंधी आर्थिक सहायता	2801	16.67	...	16.67	10.00	...	10.00
12. पावरग्रिड को अनुदान	2801	50.00	...	50.00	50.00	...	50.00	40.00	...	40.00
13. उत्तर पूर्वी राज्यों में जनजातीय गांवों का विद्युतीकरण	2801	12.53	...	12.53
14. उत्तर पूर्वी क्षेत्र और सिक्किम में उप-पारिषण और वितरण निर्माण कार्य	3601	46.80	...	46.80
जोड़-सामान्य		402.26	47.30	449.56	458.96	43.50	502.46	454.82	45.27	500.09
थर्मल विद्युत उत्पादन										
15. बदरपुर थर्मल पावर स्टेशन										
15.01 राजस्व व्यय	2801	...	701.00	701.00	...	956.00	956.00	...	971.00	971.00
15.02 घटाइए-राजस्व प्राप्तियां	2801	...	-700.00	-700.00	...	-955.00	-955.00	...	-970.00	-970.00
15.03 निवल व्यय		...	1.00	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00
15.04 बदरपुर तापीय विद्युत केन्द्र का विस्तार	4801	10.00	...	10.00	10.70	...	10.70	9.31	...	9.31
जोड़		10.00	1.00	11.00	10.70	1.00	11.70	9.31	1.00	10.31
पन बिजली उत्पादन										
16. पन बिजली परियोजनाएं										
16.01 सरदार सरोवर परियोजना	4801	36.38	...	36.38	36.38	...	36.38	36.27	...	36.27
पारिषण और वितरण										
17. ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (कुटीर ज्योति)	2801	65.00	...	65.00	65.00	...	65.00	63.00	...	63.00
18. भार पारिषण केन्द्र	4801	0.05	...	0.05	0.15	...	0.15
19. राष्ट्रीय उच्च वोल्टता प्रत्यक्ष धारा परियोजना	4801	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00
जोड़		67.00	...	67.00	67.05	...	67.05	63.15	...	63.15

(करोड़ रुपए)										
मुख्य शीर्ष	बजट 2000-2001			संशोधित 2000-2001			बजट 2001-2002			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
20. अन्तर्राज्यीय पारेषण लाइनें										
20.01 राज्य सरकारों को ऋण	7601	10.00	...	10.00	...	10.00
21. ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (राज्य आयोजना)	7601	5.20	...	5.20
22. उत्तर पूर्वी क्षेत्र और सिक्किम के विकास के लिए परियोजनाएं/योजनाएं	2552	7.00	...	7.00	...
	4552	464.70	...	464.70	...
23. ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (राज्य आयोजना)	4801	50.00	...	50.00	50.00	...	50.00	...
	6801	460.00	...	460.00	410.00	...	410.00	410.00	...	410.00
जोड़		460.00	...	460.00	460.00	...	460.00	...	460.00	...
जोड़ - विद्युत		985.64	48.30	1033.94	1048.29	44.50	1092.79	1495.25	46.27	1541.52
24. सरकारी उद्यमों में निवेश	4801	1217.00	...	1217.00	1252.00	...	1252.00	1579.49	...	1579.49
	6801	898.08	...	898.08	864.96	...	864.96	212.76	...	212.76
जोड़		2115.08	...	2115.08	2116.96	...	2116.96	1792.25	...	1792.25
कुल जोड़		3100.97	55.74	3156.71	3165.50	51.75	3217.25	3288.00	53.80	3341.80
ख. सरकारी उद्यमों में निवेश	विकास शीर्ष	बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़
24.01 राष्ट्रीय ता विद्युत निगम	12801	116.98	2422.42	2539.40	116.98	2350.02	2467.00	...	3006.00	3006.00
20.02 राष्ट्रीय जल विद्युत शक्ति निगम	12801	620.00	644.16	1264.16	690.00	453.36	1143.36	943.25	631.64	1574.89
24.03 विद्युत वित्त निगम	12801	11.00	...	11.00	11.00	...	11.00
24.04 दामोदार घाटी निगम	12801	...	459.90	459.90	...	100.00	100.00	...	284.00	284.00
24.05 उत्तर-पूर्वी विद्युत शक्ति निगम	12801	122.00	133.26	255.26	122.00	60.00	182.00	...	86.72	86.72
24.06 नाथपा झाकरी तापीय निगम	12801	562.00	390.00	952.00	562.00	295.00	857.00	562.00	332.00	894.00
24.07 टिहरी जल विकास निगम	12801	386.00	362.57	748.57	351.00	295.34	646.34	200.00	1028.17	1228.17
24.08 पावर ग्रिड निगम	12801	108.10	2666.90	2775.00	74.98	2086.16	2161.14	...	2869.00	2869.00
24.09 ग्रामीण विद्युतीकरण निगम	12801	189.00	...	189.00	189.00	...	189.00	37.00	...	37.00
24.10 विद्युत व्यापार निगम	12801	50.00	...	50.00
जोड़		2115.08	7079.21	9194.29	2116.96	5639.88	7756.84	1792.25	8237.53	10029.78
ग. आयोजना परिव्यय										
केन्द्रीय क्षेत्र की आयोजना विद्युत	12801	2640.97	7079.21	9720.18	2705.50	5639.88	8345.38	2356.30	8237.53	10593.83
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	22552	471.70	...	471.70
राज्य योजनाएं	43601	460.00	...	460.00	460.00	...	460.00	460.00	...	460.00
जोड़		3100.97	7079.21	10180.18	3165.50	5639.88	8805.38	3288.00	8237.53	11525.53

1. सचिवालय : इसमें विद्युत मंत्रालय के सचिवालय के व्यय की व्यवस्था है।

2. केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण : केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण, राष्ट्रीय विद्युत संसाधनों के नियंत्रण तथा उपयोग के संबंध में विभिन्न एजेंसियों के क्रियाकलापों के बीच समन्वय करता है। यह विद्युत साधनों का सर्वेक्षण और अध्ययन करने, विद्युत के उत्पादन, वितरण और उपयोग से संबंधित आंकड़ों को एकत्र करने और उनका रिकार्ड रखने तथा विद्युत साधनों के विकास के लिए भी उत्तरदायी है। इसमें तकनीकी नियंत्रण, आयोजना और मानीटरिंग, प्रशिक्षण, डिजाइन और सलाहकारी सेवा, क्षेत्रीय समन्वय, आदि को अद्यतन बनाने पर होने वाले व्यय के लिए व्यवस्था की गई है।

3. अनुसंधान और विकास : केन्द्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, बंगलौर विद्युत पर अनुसंधान करने में लगा है। केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान विद्युत ऊर्जा के क्षेत्र में प्रयुक्त अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय प्रयोगशाला है तथा यह विद्युत उपकरण एवं संघटकों के परीक्षण, मूल्यांकन तथा प्रमाणन के लिए स्वतंत्र प्राधिकरण के रूप में भी कार्य करता है।

4. प्रशिक्षण : इसमें राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, जो विद्युत केन्द्रों के प्रचालन और अनुसंधान के विभिन्न पहलुओं में प्रशिक्षण प्रदान करने में संलग्न है, पर होने वाले व्यय की व्यवस्था है।

5. ऊर्जा संरक्षण : इसमें ऊर्जा संरक्षण क्रियाकलापों जिसमें ऊर्जा लेखा परीक्षण, प्रदर्शन परियोजनाएं, अध्ययन, जागरूकता अभियान आदि जैसे संवर्धनात्मक क्रियाकलाप शामिल हैं, पर होने वाले व्यय के लिए व्यवस्था शामिल है।

6. राज्य विद्युत नियामक आयोग की स्थापना : उत्तर पूर्वी क्षेत्र में नियामक आयोग की स्थापना के लिए।

8. ताप विद्युत केन्द्रों के बेहतर निष्पादन के लिए प्रोत्साहन स्कीम : इसमें की गई व्यवस्था ताप विद्युत केन्द्रों के बेहतर निष्पादन के लिए और ताप विद्युत केन्द्रों के सक्षम और कम खर्चीले प्रचालन के लिए प्रोत्साहन पुरस्कार योजना एवं पारेषण और वितरण संबंधी हानियों को कम करने के लिए भी है।

9. केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग : शुल्कों को तर्कसंगत बनाने व अन्य संबंधित मामलों पर व्यय की व्यवस्था है।

12. पावरग्रिड को सहायता अनुदान : पूर्वोत्तर राज्यों में पारेषण परियोजनाओं के लिए।

15. बदरपुर ताप विद्युत केन्द्र :

15.01, 02, 03 और 04 बदरपुर ताप विद्युत केन्द्र, जिसका स्वामित्व केन्द्र सरकार के अधीन है, का प्रबंध एजेंसी आधार पर राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा किया जा रहा है। चरण I, II और III में सभी पांच इकाइयां वाणिज्यिक कार्यचालन के अधीन हैं। बदरपुर ताप विद्युत परियोजना के शेष कार्य पर होने वाले व्यय के लिए भी व्यवस्था की गई है।

17. कुटीर ज्योति कार्यक्रम : हरिजनों और आदिवासियों सहित गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले ग्रामीण निर्धनों के जीवन-स्तर में सुधार करने के लिए केन्द्र सरकार ने समाज के निर्धन वर्गों के घरों में एकल प्वाइंट बिजली के कनेक्शन प्रदान करने के लिए वर्ष 1989 में 'कुटीर ज्योति' योजना शुरू की। मार्च 1999 के अंत तक आदिवासियों एवं हरिजनों सहित ग्रामीण गरीबों को 33.58 लाख से ज्यादा एकल प्वाइंट लाइट कनेक्शन जारी किए गए हैं। वर्ष 1999-2000 के दौरान दिसम्बर, 1999 तक 1.98 लाख कनेक्शन जारी किए गए थे।

20. अन्तर्राज्यीय पारेषण लाइनें : यह स्कीम क्षेत्रीय ग्रिडों के निर्माण को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से सशक्त विद्युत प्रणाली को जोड़ने तथा उसे एक

अन्तर-संबद्ध/समेकित ढंग से संचालित करने के लिए अन्तर्राज्यीय/अन्तर-क्षेत्रीय कड़ी का निर्माण करने से संबंधित है ताकि अन्ततः एक अखिल भारतीय ग्रिड बन सके। ये स्कीमें राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को ऋण देकर क्रियान्वित की जाती है।

22. पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम में कतिपय परियोजनाओं/योजनाओं के लिए 471.70 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है।

23. **राज्य आयोजना के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण निगम** : आर. ई. सी. की स्थापना जुलाई, 1969 में एक सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी के रूप में ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं के वित्तपोषण तथा ग्रामीण विद्युत सहायताओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से की गई थी। प्रावधान को इसकी गतिविधियों के लिए इक्विटी तथा ऋण के रूप में बजटीय सहायता प्रदान करने के लिए किया गया है।

24. सरकारी उद्यमों में निवेश :-

24.01 **नैशनल थर्मल पावर कारपोरेशन (एन टी पी सी)** : केन्द्रीय क्षेत्र में एन.टी.पी.सी. की स्थापना नवम्बर, 1975 में केन्द्रीय क्षेत्र में एक ताप विद्युत उत्पादन कम्पनी के रूप में की गई जिसका मुख्य उद्देश्य कोलपिट हेड में सुपर ताप विद्युत परियोजनाओं का निर्माण करना था। 31.12.2000 की स्थिति के अनुसार निगम ने कुछ 19435 मेगावाट की क्षमता चालू की है। एन टी पी सी इस समय 12 ताप विद्युत परियोजनाओं और 7 गैस पर आधारित साइकिल विद्युत परियोजनाओं जिनकी कुल अनुमोदित क्षमता 22495 मेगावाट है, का संचालन और निष्पादन कर रहा है।

24.02 **नैशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन (एन. एच. पी. सी.)** : नैशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन (एन.एच.पी.सी.) की स्थापना केन्द्रीय क्षेत्र में पनविद्युत परियोजनाओं के तीव्र, सक्षम और कम स्वीचले रूप से पूरा करने और प्रचालित करने की दृष्टि से वर्ष 1975 में की गई थी। कारपोरेशन ने अभी तक 7 पन विद्युत परियोजनाओं का निर्माण कार्य पूरा किया है और मार्च 2000 के अन्त तक इन परियोजनाओं को पूरा करके अतिरिक्त 2193 मेगावाट सृजन क्षमता की वृद्धि की है। कारपोरेशन इस समय जम्मू और कश्मीर में दुलहस्ती परियोजना (390 मेगावाट), उत्तरप्रदेश में धौलीगंगा परियोजना, चरण- I (280 मेगावाट), निर्माण और हिमाचल प्रदेश में चमेरा चरण-II (300 मेगावाट) में संलग्न है। कारपोरेशन ने सिक्किम में तीस्ता, चरण-V (510 मेगावाट), लोकतक अधोप्रवाह (90 मेगावाट), परवती-II (800 मेगावाट) का निर्माण कार्य भी शुरू किया है। एन. एच. पी. सी. कालापोंग तथा कुरुचि परियोजनाओं का भी एजेन्सी आधार पर और इंदिरा सागर परियोजना संयुक्त उपक्रम के रूप में कार्य कर रही है।

24.03 **विद्युत वित्त निगम (पी. एफ. सी)** : वर्ष 1986 में विद्युत उत्पादन परियोजनाओं के लिए सावधि वित्त प्रदान करने के उद्देश्य से निगमित की गई थी। त्वरित उत्पादन और आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत विद्युत वित्त निगम वर्तमान ताप विद्युत ताप घरों के आधुनिकीकरण व नवीकरण तथा विद्युत दरों के जीवन विस्तार हेतु केन्द्र सरकार द्वारा दी जा रही ब्याज सबसिडी के माध्यम से रियायती दरों पर उधार देकर विद्युत उपयोगिता को सहायता प्रदान करता है। पारेषण और वितरण योजनाओं, सुधारी गई प्रणाली और उत्पादन परियोजना से अतिरिक्त क्षमता मिलने की संभावना है।

24.04 **दामोदार घाटी निगम (डी. वी. सी.)** : डी.वी.सी की स्थापना जुलाई, 1948 में सिंचाई, जलपूर्ति, अपवहन, तापीय और पन-बिजली के उत्पादन, पारेषण और वितरण के लिए स्कीमों के संवर्धन और प्रचालन के लिए की गई थी। इस समय दामोदार घाटी निगम पश्चिम बंगाल में मेजिया ताप विद्युत परियोजना (3 x 210 मेगावाट) को निष्पादित कर रहा है। यूनिट I पहली दिसम्बर, 1997 से वाणिज्यिक प्रचालनाधीन है। यूनिट II तेल से दिनांक 24 मार्च, 1997 को और कोयले से 31 मार्च, 1998 को समक्रमिक बन गया है। यूनिट तीन दिनांक 25 मार्च, 1998 को तेल से और कोयला प्रज्वलन से 17 अक्टूबर, 1998 को समक्रमिक बन गया है।

24.05 **उत्तर-पूर्वी विद्युत शक्ति निगम** : उत्तर-पूर्वी विद्युत शक्ति निगम की स्थापना उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में विद्युत विकास अभिकरण के रूप में की गई थी जिसने 625 मेगावाट की कुल स्थापित क्षमता शुरू कर दी है जिसमें असम गैस टरबाइन संयुक्त चक्र विद्युत परियोजना 291 मेगावाट, कोपीली एच.ई.परियोजना-250 मेगावाट और

अगरतला गैस आधारित परियोजना 84 मेगावाट शामिल हैं। फिलहाल यह निगम केन्द्रीय क्षेत्र के अंतर्गत मिजोरम में टयूरयल एच.ई. 60 मेगावाट और असम में कोपीली एच.ई. परियोजना चरण II (25 मेगावाट) नामक परियोजना पूर्वोत्तर परिषद, और गृह मंत्रालय के अंतर्गत नागालैंड में डोयांग पन बिजली परियोजना-75 मेगावाट और अरुणाचल प्रदेश में रंगानदी परियोजना (405 मेगावाट) पर काम चल रहा है। इसके अतिरिक्त अरुणाचल प्रदेश में कामेंग पन बिजली परियोजना (210 मेगावाट), मिजोरम में तुईवली पन बिजली परियोजना (210 मेगावाट), मणिपुर में तिपाईमुख पन बिजली परियोजना (150 मेगावाट) और असम में लोअर कोपीली पन बिजली परियोजना (150 मेगावाट) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान निपको द्वारा शुरू की जाने वाली नई परियोजनाएं प्रस्तावित हैं।

24.06 **नाथपा झाकरी विद्युत निगम (एन. जे. पी. सी.)** : हिमाचल प्रदेश के सतलज बेसिन में जल विद्युत पॉवर परियोजनाओं की योजना बनाने, संवर्धन करने, संचालन करने, निष्पादन करने, कार्यान्वयन एवं अनुरक्षण के लिए मई, 1988 में निगमित किया गया था। निगम वर्तमान में नाथपा झाकरी एच.ई.पी (1500 मेगावाट) संचालित कर रहा है। यह परियोजना भारत सरकार और हिमाचल प्रदेश सरकार का संयुक्त उद्यम है। दोनों भागीदार परियोजना की लागत को क्रमशः 75:25 के अनुपात में बांटेंगे।

24.07 **टिहरी पन बिजली विकास निगम (टी.एच.डी.सी.)** : टिहरी पन-बिजली विकास निगम टिहरी में भागीरथी नदी और इसकी सहायक नदियों के पन-बिजली संसाधनों और अनुप्रवाह के एकीकृत और कुशल उपयोग के लिए जुलाई, 1988 में भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के संयुक्त उद्यम के रूप में निगमित किया गया था। टिहरी पन बिजली विकास निगम को टिहरी पन बिजली परिसर के निर्माण का काम दिया है जिसमें (क) टिहरी बांध और एच. ई. परियोजना चरण i (1000 मेगावाट, (ख) कोटेश्वर बांध और एच. ई. परियोजना (400 मेगावाट) और (ग) टिहरी पंप भंडारण परियोजना (1000 मेगावाट) शामिल हैं। फिलहाल यह निगम टिहरी बांध और एच.ई. परियोजना चरण i (1000 मेगावाट) पर काम कर रहा है जिसे वर्ष 2002 तक चालू कर दिए जाने की संभावना है। निगम ने कोटेश्वर बांध एच. ई. परियोजना (400 मेगावाट) के कार्य को प्रारम्भ कर दिया है।

24.08 **पावर ग्रिड कारपोरेशन** : पावर ग्रिड कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड को सुदृढ़ वाणिज्यिक सिद्धान्तों के आधार पर विश्वसनीयता, सुरक्षा एवं मितव्ययिता के साथ क्षेत्र के अन्दर एवं बाहर विद्युत अन्तरण को सरल बनाने के लिए क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय ग्रिड स्थापित एवं संचालित करने हेतु 1989 में निगमित किया गया था। संसद द्वारा पारित अधिनियमों के अनुसार एन. टी. पी. सी., एन. एच. पी. सी., एन. ई. ई. पी. सी. ओ. तथा एन. एल. सी. को पारेषण प्रणाली अप्रैल, 1992 से पी. जी. सी. आई. एल. को हस्तांतरित कर दी गई। 31 मार्च 1999 की स्थितिनुसार पावरग्रिड 35119 सी किमी संचालित करते हैं। (400 केवी किलोवाट 26293 सी किमी, 220 कि. वाट के 5931 सी किमी, 132 कि. वाट के 1265 सी किमी और एच वी डी सी प्रणाली के 1630 सी किमी वाली पारेषण लाइनें 28820 एमवीए परिणामतः ट्रांसफॉर्मेशन क्षमता वाले 60 उप-केन्द्रों के वितरित की गई इस समय 132 कि.वाट से लेकर 800 कि. वाट तक के वाल्टेज स्तरों वाली लगभग 8960 सी किमी पारेषण लाइने तथा कण्डों सहित 9 उप-केन्द्र निर्माणाधीन हैं। एच वी डी सी लिकों के महत्व को ध्यान में रखते हुए पी जी सी आई एल ने नवी योजना के दौरान इन लिकों के माध्यम से देश के विभिन्न विद्युत क्षेत्रों को अंत संबंधित करने के लिए एक योजना तैयार किया है।

24.09 **ग्रामीण विद्युतीकरण निगम - प्रणाली सुधार** : यह व्यवस्था ओ ई सी एफ की सहायता से ग्रा. वि. नि. के माध्यम से नौ राज्यों में प्रणाली सुधार और छोटी पन बिजली परियोजनाओं के लिए है। यह लाइन क्षतियों को कम करने और विद्युत प्रणाली सुधार परियोजना के माध्यम से आपूर्ति की गुणवत्ता सुधारने में सहायता देगा। छोटी पनबिजली परियोजनाएं स्थानीय क्षेत्रों में विद्युत उत्पादन बढ़ाने में सहायता करेंगी।

24.10 **विद्युत व्यापार निगम** के लिए इक्विटी निवेश के रूप में 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।